यह अनुमान लगाया गया है कि देश में कुल 141.41 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42.92 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जी हां, वनीकरण और वृक्षारोपण के एक बृहत कार्यक्रम के माध्यम से देश में बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने के मुख्य उद्देश्य से 1985 में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था। तथापि, बोर्ड को सौंपे गये उत्तरदायित्व में बंजरभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना शामिल नहीं है। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया जिसके अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत बंजरभूमि सहित भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां की जाती हैं। 31.3.94 तक 12,662 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण के अंतर्गत लाया गया है और निजी भूमि पर रोपण हेतु 5029.61 मिलियन बीजांकुरों का वितरण किया गया है।

जुलाई, 1992 में, राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय में बंजरभूमि विकास विभाग के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड को वनेतर बंजरभूमि के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस संदर्भ में बोर्ड निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना

(4) बंजरभूमि विकास कार्य दल

(5) निवेश संवर्धन योजना

(ङ) व (च) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड बायोमास उत्पादन विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे में वृद्धि के लिए बंजरभूमि के सतत् विकास के लिए उत्तरदायी है। बंजरभूमि के लिए स्पष्ट लक्ष्य विभिन्न केन्द्र और राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर है।

मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर में ह्रास

2820. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में निरंतर ह्रास हो रहा है और गांवों में अनेक हैंड पम्प ठप्प हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार पेय जल की आपूर्ति बनाये रखने और भूमिगत जल स्तर में ह्रास को रोके जाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजे हैं; यदि हां, तो कितने और उन प्रस्तावों की स्वीकृति संबंधी स्थिति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच० पटेल: (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में भूजल की निकासी की तुलना में इसकी कम संपूर्ति के कारण जल स्तर नीचे चला जाता है जिसके कारण ट्यूबवैलों की क्षमता में कमी हो जाती है अथवा वे सूख जाते हैं।

(ख) इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) मध्य प्रदेश में जल एकत्रीकरण ढांचो के लिए योजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की गई है। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(लाख रु० में)

जिला	अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत	रिलीज की गई निधियां	सूचित खर्च
झाबुआ	111.080	11.080	130.750
राजगढ़	143.060	143.060	170.170
शहडोल	314.600	306.870	301.430

(2) 2 अगस्त 1994 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सरकारों से केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पता लगाए गए "डार्क एंड ग्रे" खंडों में भूजल की अत्यधिक निकासी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित जल संरक्षण और जल सम्पूर्ति परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं।

(लाख रु० में)

क्रमांक	जिला	लागत
1.	शाजापुर	270.00
2.	धार	1120.88
3.	कराहल खंड (मोरैना)	513.39
4.	मांडला	198.00
5.	राजगढ़	656.00
6.	राजनंद गांव	500.00
7.	देवास	103.73

राजगढ़ परियोजना के लिए 25 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत और रिलीज की गई है जिसका उपयोग मॉडल योजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। उक्त योजनाओं को परियोजना क्षेत्र के अन्य भागों में भी चलाया जा सकता है।

82nd Annual Session of Indian Science Congress

2821. SHRI V. NARAYANASAMY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the 82nd Annual Session of Indian Science Congress was opened by the Prime Minister at Calcutta recently;

(b) if so, the number of persons who participated at this session; and

(c) the number of foreign scientists who participated at the discussion and what was the outcome of discussion at this meet, alongwith the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) Yes Sir.

(b) About 6000 persons attended the various sessions of the Science Congress.

(c) 33 Foreign scientists attended the Congress. During the session various sections, committees and fora discussed issues related to the focal theme "Science, Technology & Industrial Development in India." The reommendations of the Congress are under finalisation by the Indian Science Congress Association (ISCA).

Collaborative Research and Development Programme with Asian Countries

2822. SHRI S. MADHVAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to launch a collaborative research and development programme with Asian countries, and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND SPACE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) and (b) Collaborative R&D programmes are being developed with a number of Asian countries, including Japan, China, Singapore and the Association of South East Asian Nations (ASEAN). On our collaboration with Japan projects are being developed in the areas of Molecular Structure, Spectroscopy & Dynamics, New Materials, Modern Biology & Biotechnology, Manufacturing Sciences, and Astronomy & Astrophysics under India-Japan Cooperative Science programme initiated with the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Exchange visits are being undertaken with China on Lasers, Chemical Technology, Materials Science, Biotechonology signed in January 1995, discussions have been initiated on